

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 009/2018 (GCMS 2018/00142)	दायर दिनांक 09.01.2018	निर्णय दिनांक 11.02.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

श्रीमती कमला बाई पत्नि प्रभुनाथ जाति नाथ आयु वयस्क
निवासी लोटियाना तहसील इंगला जिला चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट**बनाम**

सरकार जरिये उप तहसीलदार मंगलवाड तहसील इंगला जिला
चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

**-:: अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध न्यायालय उप तहसीलदार मंगलवाड प्रकरण संख्या
604/2017 अतिक्रमण तारीख आदेश 11.10.2017 ::-**

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट
श्री भेरुलाल सालवी

अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अधिवक्ता

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 11.10.2017 न्याय, नियम एव वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का लोटियाना द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने मौजा लोटियाना की चरनोट आराजी नम्बर 506 रकबा 0.01 हेक्टर पर संवत 2074 में नाजायज कब्जा कर पडत कर रखी है जिससे अतिक्रमण की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। उक्त आशय का नोटिस दिनांक 11.10.2017 का जारी किया गया नोटिस की पालना में अपीलान्ट स्वयं हाजिर हुयी व जवाब हेतु अवसर चाहा फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर साईक्लोस्टाईल निर्णय जिसमें खानापूर्ति कर पारित कर बेदखली एवं पेनाल्टी का आदेश पारित कर दिया। जो आदेशिका के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये,



उसके संबंध में अपीलान्ट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है जो नियमन योग्य कब्जा था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की अपीलान्ट को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम अपीलान्ट दिनांक 11.10.2017 को नोटिस की पालना में उपस्थित हुयी व जवाब हेतु अवसर चाहा फिर भी जवाब का अवसर दिये बिना उसी दिन निर्णय व आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी दिनांक 27.12.2017 को हुई। जिस पर दिनांक 27.12.2017 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल दिनांक 28.12.2017 को ही प्राप्त की, जिससे बाद जानकारी अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद पेश है, अंत में अपीलांट की और से प्रार्थना की गई कि अपील अपीलांट स्वीकार पर भी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 11.10.2017 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलांट के नाम जारी किए जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर उपतहसीलदार मंगलवाड के पत्रांक/राजस्व/2018/13 दिनांक 02.02.2018 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 604/2017 अनवानी सरकार बनाम कमलाबाई पत्नि प्रभुलाल जाति नाथ निवासी लोठियाणा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जवाब अपील को रिकार्ड पर लिया गया। अपने जवाब में पैरोकार सरकार ने अपील में वर्णित तथ्यों से इन्कार कर बताया की अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, एवं अपील अपीलांट विलम्ब से प्रस्तुत होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य है।

दिनांक 11.02.2021 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 27.12.2017 तक की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं



विधिक सलाह प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जो कि बाद तामील पत्रावली में संलग्न है। एवं अपीलांट बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई जिससे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स आदेश पारित किया ऐसी स्थिति में अपीलांट को आदेश दिनांक 11.10.2017 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिक्टल में निवेदन किया कि अपीलांट स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही अपीलांट की अनुपस्थित बताकर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया। एवं अपीलांट निरक्षर महिला है ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 11.10.2017 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में दोनो अपीलों में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए, उसके संबंध में अपीलांट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बगैर अपीलांट का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल किए जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा



बिलानाम दर्ज रेकार्ड होकर राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिससे उक्त विवादित भूमि नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार विवादित भूमि का आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः उपतहसीलदार, मंगलवाड़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया विवादित आराजीयात पर अपीलांट का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely. -

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or



(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both : Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

विवादित भूमि राजकीय भूमि दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर उप तहसीलदार मंगलवाड ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांत स्वयं द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। राजकीय भूमि अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही पत्रावली पर अपीलांत द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलांत का विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार को कोई हक-हकूक निहित है। अपीलांत्स द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित



किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2017 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार, मंगलवाड के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मंगलवाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

